

**पंचायती राज मंत्रालय**

मांग संख्या 71

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3461.46	0.63	3462.09	7000.00	0.70	7000.70	3400.00	0.69	3400.69	94.00	0.75	94.75	
<b>पूँजी</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	<b>3461.46</b>	<b>0.63</b>	<b>3462.09</b>	<b>7000.00</b>	<b>0.70</b>	<b>7000.70</b>	<b>3400.00</b>	<b>0.69</b>	<b>3400.69</b>	<b>94.00</b>	<b>0.75</b>	<b>94.75</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	14.88	0.63	15.51	25.00	0.70	25.70	22.00	0.69	22.69	25.00	0.75	25.75
<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>													
2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3. मीडिया और प्रचार	2515	14.43	...	14.43	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	2.18	...	2.18	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
6. ग्रामीण व्यापार केंद्र	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7. राज्यों को संसाधन सहायता	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें</b>													
8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना													
8.01 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.02 अवसंरचना विकास	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2515	432.24	...	432.24	44.00	...	44.00	44.00	...	44.00	50.00	...	50.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	3602	2.42	...	2.42	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़		434.66	...	434.66	44.00	...	44.00	44.00	...	44.00	50.00	...	50.00
10. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें</b>		<b>434.66</b>	...	<b>434.66</b>	<b>44.00</b>	...	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	...	<b>44.00</b>	<b>50.00</b>	...	<b>50.00</b>
11. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता का अंतरण	2515	0.32	...	0.32	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अंशदान	2515	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
<b>जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>		<b>451.67</b>	...	<b>451.67</b>	<b>69.00</b>	...	<b>69.00</b>	<b>58.00</b>	...	<b>58.00</b>	<b>59.00</b>	...	<b>59.00</b>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	
<b>राज्य योजनागत स्कीमें</b>													
14. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	2552	...	...	590.00	...	590.00	285.00	...	285.00	...	...	...	
	3601	2800.00	...	2800.00	5310.00	...	5310.00	2552.00	...	2552.00	...	...	
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>जोड़</b>	<b>2800.00</b>	...	<b>2800.00</b>	<b>5900.00</b>	...	<b>5900.00</b>	<b>2837.00</b>	...	<b>2837.00</b>	...	...	
15. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2552	...	...	110.00	...	110.00	55.00	...	55.00	...	...	...	
	3601	194.91	...	194.91	896.00	...	896.00	428.00	...	428.00	...	...	
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>जोड़</b>	<b>194.91</b>	...	<b>194.91</b>	<b>1006.00</b>	...	<b>1006.00</b>	<b>483.00</b>	...	<b>483.00</b>	...	...	
<b>जोड़-राज्य योजनागत स्कीमें</b>		<b>2994.91</b>	...	<b>2994.91</b>	<b>6906.00</b>	...	<b>6906.00</b>	<b>3320.00</b>	...	<b>3320.00</b>	...	...	
<b>कुल जोड़</b>		<b>3461.46</b>	<b>0.63</b>	<b>3462.09</b>	<b>7000.00</b>	<b>0.70</b>	<b>7000.70</b>	<b>3400.00</b>	<b>0.69</b>	<b>3400.69</b>	<b>94.00</b>	<b>0.75</b>	<b>94.75</b>
<b>विकास शीर्ष</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. बा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
<b>केन्द्रीय योजना:</b>													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	14.88	...	14.88	25.00	...	25.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	451.67	...	451.67	69.00	...	69.00	58.00	...	58.00	59.00	...	59.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>466.55</b>	...	<b>466.55</b>	<b>94.00</b>	...	<b>94.00</b>	<b>80.00</b>	...	<b>80.00</b>	<b>94.00</b>	...	<b>94.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) राज्य हिस्सा	43601	2800.00	...	2800.00	5900.00	...	5900.00	2837.00	...	2837.00	...	...	...
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43601	194.91	...	194.91	1006.00	...	1006.00	483.00	...	483.00	...	...	...
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>2994.91</b>	...	<b>2994.91</b>	<b>6906.00</b>	...	<b>6906.00</b>	<b>3320.00</b>	...	<b>3320.00</b>	...	...	...
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना :</b>													
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)</b>													
<b>जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना</b>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>3461.46</b>	...	<b>3461.46</b>	<b>7000.00</b>	...	<b>7000.00</b>	<b>3400.00</b>	...	<b>3400.00</b>	<b>94.00</b>	...	<b>94.00</b>

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. मीडिया एवं प्रचार का अभिप्राय श्रवण एवं दृश्यन प्रचार तथा मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोगों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।
5. कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन: उन शैक्षणिक संस्थाओं को जिन्हें ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व मूल्यांकन का विशेष अनुभव हो, पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं मुख्यतः बेहतर नीति निर्धारण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग हेतु कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
9. केंद्रीय आयोजना के अंतर्गत आरजीपीएसए पात्रता पूरी करने के अध्यक्षीन चुनिंदा जिला परिषदों और ग्राम परिषदों की प्रजातंत्रवादी रूप से सहायता करेगा। पंचायतों को केंद्र से 2015-2020 की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित अनुदानों में दी गई सहायता जारी रहेगी। राज्यों से पंचायतों को संसाधनों की आपूर्ति करने की आशा भी की जाती है।
10. ई-पंचायत पर परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी।
11. यूएन सहायता प्राप्त परियोजना: यूएनडीपी द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
12. स्थानीय अभिशासन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने हेतु प्रावधान है।
14. वित्त्ा वर्ष 2015-16 से, राज्य सरकारों द्वारा संसाधनों के इनके उच्चतर स्तर से आवश्यक सहायता दी जाएगी।